Daily Current Affairs

Date : 09 July, 2026

UTKARSH CLASSES CIVIL SERVICES

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	‘इंटरनेशनल सोलर अलायंस और राजस्थान सरकार’ के मध्य समझौता
2.	राजस्थान में पहली बार ‘विदेश संपर्क – स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस’ का आयोजन
3.	राजस्थान की ‘मुखबिर प्रोत्साहन योजना’
4.	‘सुयोग’ योजना का पायलट प्रोजेक्ट
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. राजस्थान में ‘स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी’ 2. अंशुमान चौधरी, अन्वी राठौर और मनन शर्मा 3. 6th राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (RDTM - 2026) 4. मारवाड़ ट्रैवल मार्ट (MTM) का प्रथम संस्करण 5. राजस्थान सरकार का नया बजट मैनुअल – 2026 6. दर्शना राजपुरोहित 7. ‘नुकरा’ : राजस्थान में घोड़े की नस्ल 8. प्रथम राज्य स्तरीय सीनियर पैरा कबड्डी चैंपियनशिप 9. 'महिला सुरक्षा संकल्प अभियान' 10. ऑपरेशन गरुड़ व्यूह – 2 11. ऑपरेशन त्रिनेत्र
6.	कामराजर बंदरगाह
7.	भारत में इथेनॉल मिश्रण
8.	प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक
9.	पीएम-सेतु
10.	ट्राइबएक्स
11.	प्रंबानन मंदिर
12.	गुवाहाटी घोषणा
13.	प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा
14.	भारत-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट
15.	मिशन दृष्टि: भारत का पहला ऑप्टोसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह
16.	ब्रह्मोस मिसाइल

राजस्थान परिदृश्य

‘इंटरनेशनल सोलर अलायंस और राजस्थान सरकार’ के मध्य समझौता

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान सरकार और इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) ने ‘फ्रेमवर्क फॉर एक्शन-एडवांस क्लीन एनर्जी, ड्रिवन सस्टेनेबल डवलपमेंट’ पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिन्दु:

- राजस्थान ISA के साथ इस प्रकार का समझौता करने वाला देश का पहला राज्य है।
- **हस्ताक्षर :** जयपुर में राजस्थान ऊर्जा सचिव आरती डोगरा एवं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक आशीष खन्ना द्वारा।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

समझौते के मायने :

- **एनर्जी ट्रांजिशन प्लान :** इस हस्ताक्षरित 'फ्रेमवर्क फॉर एक्शन' के माध्यम से राजस्थान के लिए वर्ष 2030-2035 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एनर्जी ट्रांजिशन प्लान तैयार किया जाएगा।
- इस प्लान में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, प्रसारण एवं वितरण तंत्र के सुदृढीकरण, ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण, ऊर्जा दक्षता, माँग प्रबंधन, निवेश योग्य परियोजनाओं की पहचान, ऊर्जा मॉडलिंग, संस्थागत क्षमता निर्माण तथा आवश्यक नीतिगत सुधारों जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा।
- **AI एण्ड एनेबल्ड डिजिटाइजेशन :** इस 'फ्रेमवर्क फॉर एक्शन' के अंतर्गत AI एण्ड एनेबल्ड डिजिटाइजेशन कार्य किया जाएगा। विशेष रूप से अजमेर विद्युत वितरण निगम में डिजिटल ट्विन तकनीक पर आधारित पायलट परियोजना प्रारम्भ की जाएगी, जिससे विद्युत माँग का सटीक आकलन, नेटवर्क की बेहतर योजना, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रभावी समावेशन तथा उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024 :

- **मुख्य उद्देश्य :** वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देना।
- इस नीति के तहत् वर्ष 2029-30 तक 115 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा/सौर पार्कों के बुनियादी ढाँचे के प्रबंधन एवं विकास के लिए राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड (RRECL) की स्थापना की गई है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA)

- ISA की परिकल्पना भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के 21वें सम्मेलन (COP-21) के दौरान की गई।
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी लागत को कम करके सौर विकास को बढ़ावा देना है।
- **मुख्यालय :** गुरुग्राम, हरियाणा।
- **महानिदेशक :** आशीष खन्ना।

ISA द्वारा आरंभ की गई प्रमुख पहलें:

- **सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेण्टर (STAR-C) पहल :** इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के लिए ISA सदस्य देशों के भीतर संस्थागत क्षमताओं का एक मजबूत नेटवर्क बनाना है।
- **वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG) पहल :** इसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पादित सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की आवश्यकता को पूरा करना है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राजस्थान में पहली बार 'विदेश संपर्क – स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' का आयोजन

चर्चा में क्यों?

- 16 जुलाई, 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य बिन्दु:

- **आयोजक :** विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से।
- **नोडल विभाग :** राजस्थान फाउंडेशन एवं डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज़ राजस्थानी अफेयर्स (DoRA)।
- **कार्यक्रम का उद्देश्य :** सुरक्षित एवं वैध प्रवासन के प्रति लोगों और संबंधित हितधारकों को जागरूक करना, फर्जी एजेंटों और अवैध प्रवासन के तरीकों से बचाव के उपायों की जानकारी देना, विदेश मंत्रालय की कांसुलर, पासपोर्ट, वीजा एवं प्रवासी भारतीयों से संबंधित योजनाओं और पहलों की जानकारी उपलब्ध कराना, विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों एवं श्रमिकों के हितों और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाना।

- उल्लेखनीय है कि राजस्थान में यह कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड तथा आंध्र प्रदेश में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

विदेश संपर्क – स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस:

- **शुरुआत :** विदेश मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में 'विदेश संपर्क' कार्यक्रम के तहत।
- इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मामलों, प्रवासी भारतीय कल्याण और सुरक्षित गतिशीलता पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बेहतर बनाना है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राजस्थान की 'मुखबिर प्रोत्साहन योजना'

चर्चा में क्यों?

- **हाल ही में, आबकारी विभाग ने 'मुखबिर प्रोत्साहन योजना' के तहत वर्षों से लंबित 30 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए लगभग ₹18 लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान की।**

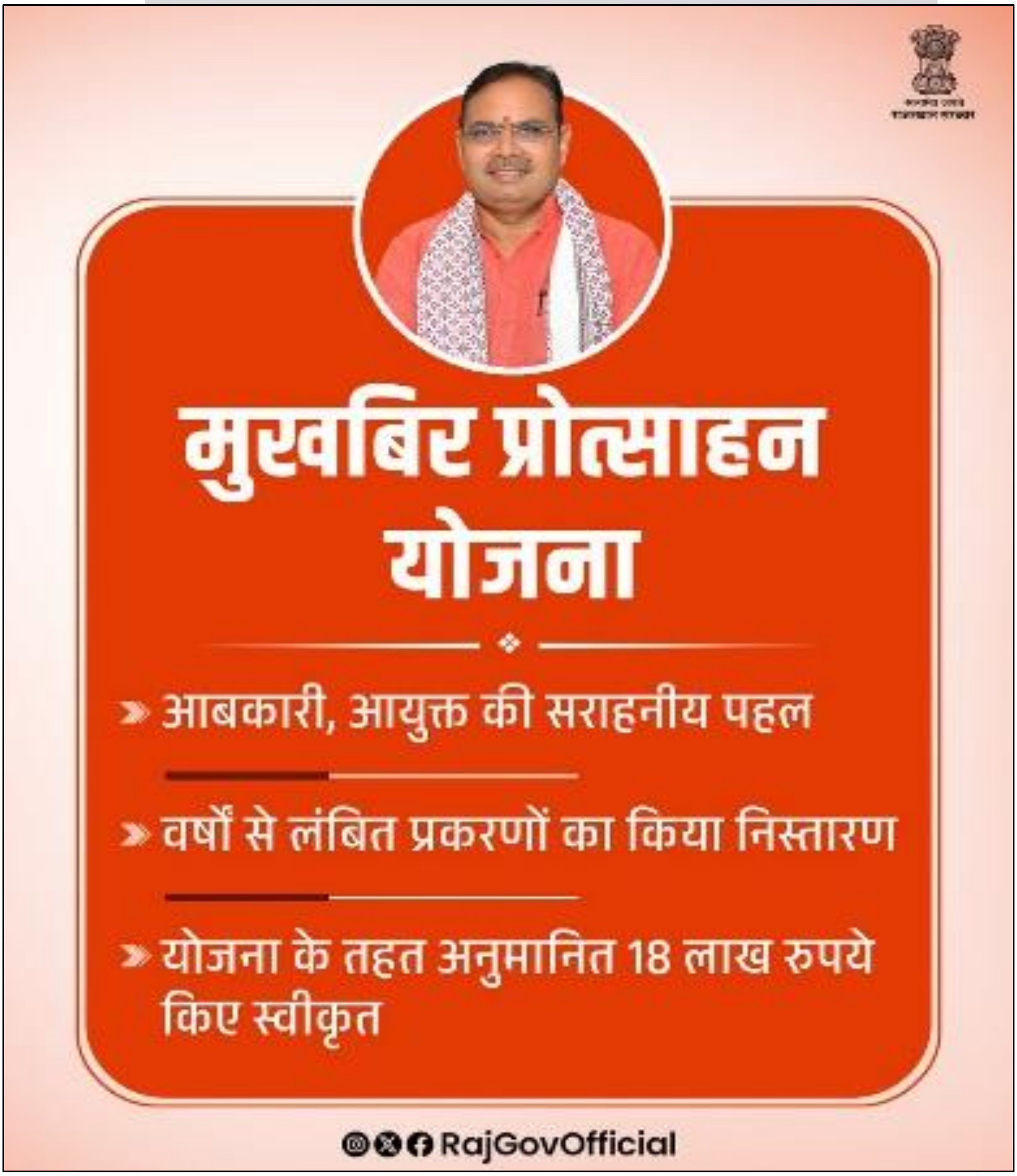

मुख्य बिन्दु:

- **लाभान्वित जिले :** श्री गंगानगर, अलवर, डूंगरपुर, उदयपुर, सीकर, अजमेर, राजसमन्द, चूरू, बीकानेर और झुंझुनूं।
- ज्ञातव्य है कि आबकारी विभाग में मुखबिर प्रोत्साहन योजना के वर्षों से लंबित प्रकरणों के अल्प अवधि में निस्तारण से मुखबिर लाभान्वित हुए है, जिससे अवैध मदिरा संबंधी विश्वसनीय सूचनाओं की वृद्धि हुई है।
- संबंधित जिला आबकारी अधिकारी की अनुशंषा पर निरोधात्मक कार्यवाहियों के तहत मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई के लिए संबंधित मुखबिर को प्रोत्साहन अथवा रिवार्ड राशि प्रदान करने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में मुखबिर द्वारा दी गई समस्त सूचना को पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है।
- राज्य सरकार के वित्त विभाग के निर्देशानुसार मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत मुखबिर द्वारा प्रदत्त सूचना ₹10 लाख अथवा उससे अधिक की निर्विवाद अनुमानित राजस्व हानि को रोकने में सहायक होने पर संबंधित सूचना प्रदाता को 4 प्रतिशत तक रिवार्ड राशि प्रदान करने का प्रावधान है।
- **अधिकतम राशि :** ₹15 लाख तक।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

'सुयोग' योजना का पायलट प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा 10 जुलाई, 2026 से 'सुयोग' (SUYOG) योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने के निर्देश जारी किए गए।

मुख्य बिन्दु:

- **पायलट प्रोजेक्ट :** जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र तथा बाराँ जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में।
- **योजना का उद्देश्य :** युवाओं को खेलों के माध्यम से एक संगठित मंच उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें खेल गतिविधियों के साथ-साथ शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार तथा सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के अवसरों से भी जोड़ा जा सके।
- **अभियान :** यह योजना 'माई भारत' अभियान के अनुरूप संचालित की जाएगी।
- प्रारंभिक चरण में युवाओं को क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी आदि खेलों से जोड़ा जाएगा।
- इस योजना को CMSDC प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा। CMSDC (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड सर्विस डिलीवरी) राजस्थान वित्त विभाग के अंतर्गत एक प्रमुख तकनीकी और प्रशासनिक इकाई है। इसका मुख्य कार्य विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों, वित्तीय योजनाओं और सरकारी सेवाओं की तकनीकी निगरानी करना है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

न्यूज़ इन शॉर्ट्स

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**राजस्थान में 'स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी'** ■ हाल ही में, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश की सरकारी और निजी स्कूलों की प्रभावी मॉनिटरिंग और छात्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी' के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। ■ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी (SSSA), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) - 2020 के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) में स्थापित किया जाने वाला एक स्वतंत्र और स्वायत्त नियामक निकाय है। ■ इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
2.	**अंशुमान चौधरी, अन्वी राठौर और मनन शर्मा** ■ जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी (शटलर) अंशुमान चौधरी, अन्वी राठौर और मनन शर्मा का चयन भारतीय जूनियर बैडमिंटन टीम में हुआ। ■ ये तीनों खिलाड़ी 8 से 13 सितंबर, 2026 तक चीन के चेंगदू में आयोजित होने वाली बैडमिंटन एशिया अंडर-15 और अंडर-17 जूनियर चैंपियनशिप - 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ■ वर्ग : अंशुमान चौधरी अंडर-17 बॉयज सिंगल्स, अन्वी राठौर अंडर-15 और अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स तथा मनन शर्मा अंडर-15 मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा।
3.	**6th राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (RDTM - 2026)** ■ आयोजन : 17 से 19 सितंबर, 2026 ■ आयोजन स्थल : बी.एम. बिड़ला कन्वेंशन सेंटर, जयपुर। ■ आयोजक : फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (FHTR) और राजस्थान पर्यटन विभाग। ■ महत्त्व : यह राजस्थान का एक प्रमुख बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) इवेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को देश के सबसे पसंदीदा डोमेस्टिक और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है।

4.	**मारवाड़ ट्रैवल मार्ट (MTM) का प्रथम संस्करण** ■ **आयोजन :** 20 से 22 सितंबर, 2026 तक। ■ **आयोजन स्थल :** जोधपुर। ■ मारवाड़ क्षेत्र के पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के दृष्टिकोण से आयोजित मारवाड़ ट्रैवल मार्ट (MTM) का मुख्य उद्देश्य मारवाड़ और थार की समृद्ध विरासत, संस्कृति, और ग्रामीण पर्यटन को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है।
5.	**राजस्थान सरकार का नया बजट मैनुअल - 2026** ■ राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने हाल ही में राज्य की बजट प्रणाली को बदलने और आधुनिक बनाने के लिए नया ड्राफ्ट बजट मैनुअल - 2026 तैयार किया। ■ इस नए मैनुअल का मुख्य उद्देश्य बदलते समय और बजट प्रक्रियाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण को ध्यान में रखते हुए बजट निर्माण, उपयोग और संचालन को अधिक सरल, वित्तीय रूप से सशक्त, जवाबदेह तथा पारदर्शी बनाना है। ■ नए मैनुअल के तहत IFMS (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) आधारित ई-बजट प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है। ■ नए मैनुअल में पहली बार ग्रीन बजट, चाइल्ड बजट, एग्रीकल्चर बजट, SDGs आधारित योजना प्रावधान, पूल बजट, यूनिफाइड पीडी अकाउंट और SNA-SPARSH जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं।
6.	**दर्शना राजपुरोहित** ■ पाली निवासी दर्शना राजपुरोहित ने दिल्ली के संसद भवन में 3 और 4 जुलाई, 2026 को आयोजित 'राष्ट्रीय युवा संसद 3.0' में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ■ दर्शना ने सदन में सांसद प्रज्ञा ठाकुर की भूमिका निभाते हुए महिला सशक्तीकरण एवं समान प्रतिनिधित्व विधेयक, 2026 पेश किया।

7.	**‘नुकरा’ : राजस्थान में घोड़े की नस्ल** ■ हाल ही में, बीकानेर स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र (NRCE) ने नुकरा नस्ल के आधिकारिक पंजीकरण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। ■ यदि सभी तकनीकी और वैज्ञानिक औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तो नुकरा भारत की 9वीं आधिकारिक पंजीकृत घोड़ा नस्ल बन जाएगी। ■ यह घोड़ा पूरी तरह से दूधिया सफेद होता है। इसकी नाक और होंठों का रंग हल्का गुलाबी होता है। ■ नुकरा घोड़ों की औसत ऊँचाई लगभग 155 से 170 सेंटीमीटर तक होती है।
8.	**प्रथम राज्य स्तरीय सीनियर पैरा कबड्डी चैंपियनशिप** ■ भरतपुर में आयोजित ‘राज्य स्तरीय सीनियर पैरा कबड्डी चैंपियनशिप’ में पुरुष वर्ग में अजमेर और महिला वर्ग में जयपुर ने खिताब जीता। ■ **संस्करण :** प्रथम संस्करण।
9.	**'महिला सुरक्षा संकल्प अभियान'** ■ 'महिला सुरक्षा संकल्प अभियान' राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू किया गया एक विशेष जन-जागरूकता अभियान है। ■ जुलाई, 2026 को 'महिला सुरक्षा संकल्प’ के रूप में मनाया जा रहा है।
10.	**ऑपरेशन गरुड़ व्यूह - 2** ■ युवाओं और समाज को नशे के जाल से बचाने के लिए कोटा पुलिस द्वारा चलाया गया विशेष अभियान।
11.	**ऑपरेशन त्रिनेत्र** ■ राजस्थान पुलिस द्वारा मादक पदार्थों (ड्रग्स) के तस्करों और नशा माफियाओं के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान।

राष्ट्रीय परिदृश्य

कामराजर बंदरगाह

चर्चा में क्यों?

- विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाद कामराजर बंदरगाह भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है जिसने अपने कैपिटल ड्रेजिंग फेज VI परियोजना के सफल समापन के बाद 18 मीटर की ड्राफ्ट क्षमता हासिल कर ली है।

मुख्य बिन्दु:

- ड्राफ्ट क्षमता से तात्पर्य उस अधिकतम जल गहराई से है जो कोई बंदरगाह जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और ठहराव के लिए प्रदान कर सकता है।
- पूर्व में इसे एनोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था, यह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर चेन्नई से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।
- इसे 1999 में भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के तहत एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था।

MCQ:

Q. कामराजर बंदरगाह भारत के किस राज्य में और किस तट पर स्थित है?

(A) केरल के पश्चिमी तट पर

(B) तमिलनाडु के पूर्वी तट पर

(C) आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर

(D) ओडिशा के पूर्वी तट पर

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

आर्थिक घटनाक्रम

भारत में इथेनॉल मिश्रण

चर्चा में क्यों?

- एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, एथेनॉल का मिश्रण 2013-14 में 1.5% से बढ़कर 2025-26 में 20% हो गया है। भारत ने 20% मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच साल पहले हासिल कर लिया है।

मुख्य बिन्दु:

- एथेनॉल (C_2H_5OH) एक एथिल अल्कोहल है जो गन्ने, मक्का, गेहूं और उच्च स्टार्च सामग्री वाली अन्य फसलों से उत्पादित होता है।
- यह एक उच्च-ऑक्टेन ईंधन है, जिसका शोधित ऑक्टेन नंबर लगभग 108.5 है, जबकि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 84.4 है।

प्रमुख चिंताएँ

- **पुराने वाहनों के साथ अनुकूलता:** इथेनॉल नमी सोखने वाला होता है, जिससे ईंधन प्रणालियों में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर पुराने वाहनों में।
- हाइग्रोस्कोपी किसी पदार्थ के उस गुण को संदर्भित करती है जिसके द्वारा वह आसपास के वातावरण से जल के अणुओं को अवशोषण या अधिशोषण के माध्यम से आकर्षित और धारण करता है।
- **उपभोक्ता विकल्पों का अभाव:** ब्राजील जैसे देशों के विपरीत, भारतीय उपभोक्ता आमतौर पर ईंधन स्टेशनों पर E10 और E20 के बीच चयन नहीं कर सकते हैं या विभेदक मूल्य निर्धारण से लाभ नहीं उठा सकते हैं।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **कम माइलेज:** कई ग्राहक दावा कर रहे हैं कि E20 ईंधन के कारण उनके वाहन का माइलेज कम हो गया है।
- **जल संकट:** गन्ने पर अत्यधिक निर्भरता, जो एक जल-गहन फसल है, जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल की कमी को और बढ़ा सकती है।
- भारत, ब्राजील के इथेनॉल मिश्रण के चरणबद्ध दृष्टिकोण का अनुसरण कर सकता है, जिसने धीरे-धीरे उच्च मिश्रणों को लचीले ईंधन वाले वाहनों, विभेदक मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता विकल्प के साथ पेश किया।

अन्य देशों में इथेनॉल मिश्रण की स्थिति

- **ब्राजील:** ब्राजील इथेनॉल के उपयोग में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है, जहां E27 इसका मानक पेट्रोल मिश्रण है और 80% से अधिक नए वाहन फ्लेक्स-फ्यूल हैं, जो E27, E30 या शुद्ध जलयुक्त इथेनॉल पर चलने में सक्षम हैं।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** अमेरिका में पूरे देश में E10 का उपयोग होता है, E15 का तेजी से विस्तार हो रहा है, और लाखों फ्लेक्स-फ्यूल वाहन हैं जो E85 तक के मिश्रण पर चलने में सक्षम हैं।
- **जापान:** जापान ने भी अपने ईंधन मिश्रण में इथेनॉल को शामिल कर लिया है। यह चरणबद्ध तरीके से E10 को लागू करके किया गया।

MODEL QUESTION:

Q. ईंधन के संदर्भ में 'हाइग्रोस्कोपी' (Hygroscopy) गुण से क्या तात्पर्य है और इसका वाहनों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

योजनाएँ एवं नीतियाँ

प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक

चर्चा में क्यों?

- शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (PGI-S) और जिलों (PGI-D) के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 की रिपोर्ट जारी की है।

मुख्य बिन्दु:

प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक

- **उद्देश्य :** स्कूली शिक्षा प्रणालियों का मूल्यांकन करने और राज्य और जिला स्तर पर प्रणालीगत सुधारों को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया।
- **PGI-S (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश):** छह डोमेन में शामिल 70 संकेतकों में 1,000 अंकों में से प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है ।
  - सीखने के परिणाम और गुणवत्ता
  - पहुँच
  - बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ
  - हिस्सेदारी
  - शासन प्रक्रियाएँ और
  - शिक्षकों की शिक्षा और प्रशिक्षण।
- **PGI-D (जिले):** यह 70 संकेतकों में 600 अंकों के आधार पर जिलों का मूल्यांकन करता है, जिन्हें 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि परिणाम, प्रभावी कक्षा संचालन, अवसंरचना सुविधाएं और छात्र अधिकार, विद्यालय सुरक्षा और बाल संरक्षण, डिजिटल शिक्षा और शासन प्रक्रिया।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

पीएम-सेतु

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन कार्यक्रम (PM-SETU) को देशव्यापी स्तर पर लागू करने की मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिन्दु:

PM-SETU

- यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 2025 में शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) को आधुनिक, उद्योग-प्रेरित कौशल विकास संस्थानों में परिवर्तित करना जो युवाओं को उभरते रोजगार अवसरों के लिए तैयार करें।

प्रमुख विशेषताएँ:

- हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत 1,000 सरकारी आईटीआई (200 हब + 800 स्पोक) का उन्नयन करें।
- क्लस्टर प्रबंधन के लिए उद्योग जगत की साझेदारी से विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) स्थापित करें।
- प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण और एडीबी और विश्व बैंक द्वारा सह-वित्तपोषण।
- अत्याधुनिक अवसंरचना, उन्नत मशीनरी और डिजिटल शिक्षण प्रणाली।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

ट्राइबएक्स (TribeX)

चर्चा में क्यों?

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइबएक्स (TribeX) का शुभारंभ किया।

मुख्य बिन्दु:

TribeX

- यह भारत की जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल शिक्षण मंच है।
- **उद्देश्य:** एक व्यापक मंच विकसित करना जो जनजातीय कला रूपों और सांस्कृतिक प्रथाओं के संरचित शिक्षण, विद्वतापूर्ण अनुसंधान और डिजिटल प्रलेखन को सुगम बनाए।
- यह यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त पांच एक वर्षीय हाइब्रिड डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें जनजातीय भाषा संताली (ओल चिकी) के पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

प्रंबानन मंदिर

चर्चा में क्यों?

- भारत इंडोनेशिया में स्थित 1,000 वर्ष से अधिक पुराने प्रंबानन मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में सहायता करेगा।

मुख्य बिन्दु:

प्रंबानन मंदिर

- यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर योग्याकार्ता के पास स्थित एक 1,000 वर्ष से अधिक पुराना प्राचीन परिसर है।
- यह वर्तमान में इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है।
- **धरोहर स्थल का दर्जा:** यह परिसर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
- **समर्पित देवता:** यह हिंदू त्रिमूर्ति, विशेष रूप से भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है।
- **कलात्मक विशेषताएँ:** यह मंदिर रामायण महाकाव्य के इंडोनेशियाई संस्करण को दर्शाने वाली जटिल पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

गुवाहाटी घोषणा

चर्चा में क्यों?

- ब्रिक्स देशों ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए गुवाहाटी घोषणापत्र को अपनाया।

मुख्य बिन्दु:

गुवाहाटी घोषणा

- **उद्देश्य:** यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सहयोग को मजबूत करती है।
- **सूचना एवं प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान:** मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने, डेटा-आधारित दृष्टिकोणों और नवीन प्रौद्योगिकियों को मजबूत करना।

MCQ:

Q. 'गुवाहाटी घोषणा' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे ब्रिक्स (BRICS) समूह के सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया है।
2. इसका मुख्य फोकस सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा

चर्चा में क्यों?

- भारत के प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा की, जिसके दौरान भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए एक संयुक्त बयान अपनाया।

मुख्य बिन्दु:

प्रमुख परिणाम

- इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बिंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया।
- भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली और एस्ट्रा बियॉन्ड-विजुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलों पर सहयोग सहित महत्त्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए ।
- दोनों देशों ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जहाज निर्माण में सहयोग, रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण (एमआरओ) सुविधाओं की स्थापना, रक्षा अनुसंधान और विकास साझेदारी की खोज और रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की।
- भारत और इंडोनेशिया ने खनिज और इस्पात आपूर्ति श्रृंखला प्रौद्योगिकी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

कनेक्टिविटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था:

- **सबांग बंदरगाह:** दोनों देशों ने समुद्री रसद और क्षेत्रीय एकीकरण को बेहतर बनाने के लिए अंडमान-एचे कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया।
- उन्होंने भारत के ONDC आर्किटेक्चर पर आधारित इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क (आईओएन) लॉन्च किया और सीमा पार क्यूआर भुगतान और दूरसंचार सहयोग की दिशा में प्रगति की।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- दोनों पक्षों ने भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच स्थानीय मुद्रा लेनदेन (एलसीटी) दिशानिर्देशों को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति का भी स्वागत किया।

भारत के लिए रणनीतिक अवसर:

- सबंग बंदरगाह पर मजबूत भूमिका निभाने से मलक्का जलडमरूमध्य के निकट भारत की समुद्री उपस्थिति बढ़ती है, जिससे पूर्वी हिंद महासागर में निगरानी में सुधार होता है और सुरक्षा मजबूत होती है।
- ब्रह्मोस का निर्यात भारत के रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देता है, आसियान बाजारों तक पहुंच का विस्तार करता है।
- इंडोनेशिया के विशाल निकल भंडार भारत को प्रमुख बैटरी खनिजों का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को बढ़ावा देता है।
- इंडोनेशिया में यूपीआई और ओएनडीसी का विस्तार भारत के फिनटेक नेतृत्व को मजबूत करता है, साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा करता है।

MODEL QUESTION:

Q. "प्रधानमंत्री की हालिया इंडोनेशिया यात्रा ने न केवल द्विपक्षीय रक्षा विनिर्माण को गति दी है, बल्कि मलक्का जलडमरूमध्य के निकट भारत की भू-राजनीतिक उपस्थिति को भी सुदृढ़ किया है।" इस कथन के आलोक में भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख परिणामों और भारत के लिए उत्पन्न रणनीतिक अवसरों का विश्लेषण कीजिए।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट

चर्चा में क्यों?

- भारत-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट के भीतर स्थित मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत के 21वें जैव विविधता भंडार के रूप में नामित किया गया है।

मुख्य बिन्दु:

- यह पदनाम जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत प्रदान किया गया है।

भारत-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट

- **भौगोलिक विस्तार:** इसमें कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड, उत्तरपूर्वी भारत (असम को छोड़कर) और वियतनाम के कुछ हिस्से, साथ ही दक्षिणी चीन के कुछ हिस्से शामिल हैं।
- **वैश्विक महत्त्व:** इसे "अपरिहार्यता" के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष 10 जैव विविधता हॉटस्पॉट में और इसे होने वाले खतरे के स्तर के मामले में शीर्ष पांच में स्थान दिया गया है।
- **उच्च प्रजाति विविधता:** इस हॉटस्पॉट में लगभग 500 स्तनधारी प्रजातियां, 1,330 पक्षी प्रजातियां, 815 से अधिक सरीसृप प्रजातियां और 500 से अधिक उभयचर प्रजातियां पाई जाती हैं।
- **भारत में अन्य जैव विविधता हॉटस्पॉट:** हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट-श्रीलंका जैव विविधता हॉटस्पॉट और सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट (भारत में निकोबार द्वीप समूह)।

MCQ:

Q. भारत का 'निकोबार द्वीप समूह' निम्नलिखित में से किस वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है?

(A) भारत-बर्मा हॉटस्पॉट
(B) सुंडालैंड हॉटस्पॉट
(C) पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट
(D) हिमालय हॉटस्पॉट

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

विज्ञान प्रौद्योगिकी

मिशन दृष्टि: भारत का पहला ऑप्टोसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह

चर्चा में क्यों?

- बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने घोषणा की है कि मिशन दृष्टि - जो दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह और भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है - से संचार टूट गया है।

मुख्य बिन्दु:

मिशन दृष्टि

- मिशन दृष्टि एक अगली पीढ़ी का, उच्च प्रदर्शन वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे पूरी तरह से भारत के निजी क्षेत्र द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- **निर्माता:** इसे बेंगलुरु स्थित डीप-टेक स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा विकसित किया गया है ।
- **प्रक्षेपण यान और स्थल:** इसे 3 मई, 2026 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था ।

मिशन का उद्देश्य:

- मौसम या रात के अंधेरे से बाधित हुए बिना उच्च ऊंचाई वाली सीमाओं और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करने में सक्षम एक संप्रभु, उपग्रह नेटवर्क का निर्माण करना।
- चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए महत्त्वपूर्ण खुफिया कमियों को दूर करना, रणनीतिक गतिरोध के दौरान विलंबित विदेशी वाणिज्यिक छवियों पर निर्भरता को समाप्त करना।

ब्रह्मोस मिसाइल

चर्चा में क्यों?

- इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के साथ दो तटीय मिसाइल बैटरियों की चरणबद्ध खरीद के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी अनुमानित लागत 200 मिलियन डॉलर है।

मुख्य बिन्दु:

ब्रह्मोस मिसाइल

- ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की, सार्वभौमिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो एक विशिष्ट प्रणाली पर काम करती है।
- मैक 2.8 की बेहद तेज गति से उड़ने वाली यह मिसाइल दुनिया की सबसे तेज परिचालन योग्य क्रूज मिसाइल होने का खिताब रखती है और वैश्विक स्तर पर निर्यात के लिए उपलब्ध एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
- **निर्माण:** इस मिसाइल का निर्माण ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा किया जाता है, जो 1998 में स्थापित एक अत्यंत सफल संयुक्त उद्यम है।
- **भारत:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की इसमें 50.5% की बहुमत हिस्सेदारी है।
- **रूस:** एनपीओ मशिनोस्ट्रोयेनिया, 49.5% हिस्सेदारी रखता है।
- **नियामक:** इस संयुक्त उद्यम संरचना के कारण, मॉस्को के पास वीटो का अधिकार बरकरार है और उसे प्रत्येक तीसरे देश को होने वाली बिक्री पर स्पष्ट रूप से सहमति देनी होगी।
- भारत से वैश्विक निर्यात: फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया।

MCQ:

Q. ब्रह्मोस एयरोस्पेस निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच एक संयुक्त उद्यम (Joint Venture) है?

(A) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) भारत और फ्रांस
(C) भारत और रूस
(D) भारत और इजराइल

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213